



2025:AHC:9655-DB

प्रकाशनार्थ स्वीकृत

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक अपील संख्या - 398 वर्ष 2018

गिराज सिंह

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: शिव शंकर यादव, शिवम द्विवेदी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: ए.जी.ए.

न्यायालय संख्या-48

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह

माननीय न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-I

(द्वारा माननीय न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह)

1. यह आपराधिक अपील अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 13, आगरा द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 320 वर्ष 2012, अंतर्गत धारा 302 भा.द.सं., थाना सिकंदरा, जनपद आगरा से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 380 वर्ष 2012 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 14.12.2017 के विरुद्ध दाखिल की गई है, जिसके द्वारा विद्वान न्यायाधीश ने अपीलार्थी को धारा 302 भा.द.सं. के अंतर्गत आजीवन कारावास और 50,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई और जुर्माना अदा न करने में व्यतिक्रम की स्थिति में, अपीलार्थी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आगे निर्देश दिया गया।

संक्षिप्त तथ्य

2. वे तथ्य जिन्होंने वर्तमान आपराधिक अपील का आधार बनाया, यह हैं कि 29.04.2012 को प्रथम सूचनादाता राम खिलाड़ी द्वारा थाना सिकंदरा, जनपद आगरा में एक मुकेश कुमार द्वारा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

लिखी गई एक लिखित रिपोर्ट दी गई थी कि वह हाट मैदान, थाना राजा खेड़ा, जिला धौलपुर का निवासी है और वर्तमान में मोहल्ला विनायक नगर, पुलिस थाना सिकंदरा में रह रहा है। 28.04.2012 को दोपहर लगभग 2.00 बजे, जब वह अपने 24 वर्षीय पुत्र राकेश और अपने बड़े पुत्र राजू के साथ अपने घर पर मौजूद था, उस समय दीवान सिंह का पुत्र गिराज (जिसे आगे 'अपीलार्थी' कहा गया है), निवासी शिव कुंज कॉलोनी, के.के. नगर, थाना सिकंदरा, जनपद आगरा वहां आया और उसके पुत्र-राकेश (जिसे आगे 'मृतक' कहा गया है) को अपने साथ ले गया। जब राकेश रात 10:00 बजे तक नहीं लौटा, तो प्रथम सूचनादाता राकेश के बारे में पूछताछ करने के लिए गिराज के घर गया, जिस पर गिराज ने उसे बताया कि राकेश दरगाह गया है। प्रथम सूचनादाता ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर राकेश की काफी खोजबीन की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आगे अभिकथन किया गया है कि जब प्रथम सूचनादाता फिर से गिराज के घर गया, तो वह मौजूद नहीं था और जब उसने खिड़की से अंदर देखा, तो उसका पुत्र चारपाई पर मृत पड़ा था और उसकी गर्दन के चारों ओर बिजली का तार लिपटा हुआ था। प्रथम सूचनादाता को संदेह था कि उसके पुत्र की हत्या गिराज ने किया है।

3. उपरोक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर, पी.डब्लू.-6, कांस्टेबल 1351 अवधेश कुमार द्वारा धारा 302 भा.द.सं. के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 320 वर्ष 2012 दर्ज किया गया था।

4. वाद दर्ज होने के बाद, वाद की विवेचना पी.डब्लू.-11, राजीव यादव द्वारा की गई। 29.04.2012 को, उसने प्रासंगिक दस्तावेजों की विषयवस्तु की प्रतिलिपि बनाई और बिजली के तार और एक चौथाई देशी शराब को कब्जे में लिया और प्रथम सूचनादाता का बयान दर्ज किया और प्रथम सूचनादाता के बताने पर घटनास्थल का निरीक्षण किया। उसने साक्षी राम कुमार और बाबू लाल के बयान भी दर्ज किए और नक्शा-नजरी, प्रदर्श क-10 तैयार किया। 30.04.2012 को, उसने पंचायतनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति की प्रतिलिपि बनाई। उसने प्रथम सूचनादाता राम खिलाड़ी के पुत्र राजू और श्रीमती माया देवी का बयान भी दर्ज किया। विवेचना के समापन और आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, विवेचना अधिकारी ने धारा 302 भा.द.सं. के अंतर्गत अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 06.05.2012, प्रदर्श क-11 प्रस्तुत किया।

5. अपीलार्थी का दोष पूरी तरह से सिद्ध करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने कुल ग्यारह साक्षीगण को परीक्षित किया है। पी.डब्लू.-1, राम खिलाड़ी (प्रथम सूचनादाता) और मृतक का पिता, पी.डब्लू.-2, श्रीमती माया देवी, मृतक की माता, पी.डब्लू.-3, बाबू लाल, पी.डब्लू.-4, राज कुमार, पी.डब्लू.-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5, राजू, मृतक का भाई, पी.डब्लू.-6, कांस्टेबल अवधेश कुमार, जिसने चिक एफ.आई.आर. तैयार किया, पी.डब्लू.-7, डॉ. अजीत बाबा, जिसने मृतक के शव-परीक्षण किया, पी.डब्लू.-8, भूरा उर्फ जलालुद्दीन, पी.डब्लू.-8ए, रामदीन, पी.डब्लू.-9, कुंवर पाल सिंह, पी.डब्लू.-10, एस.आई. मणिकांत शर्मा, पी.डब्लू.-11, राजीव यादव, वाद के विवेचना अधिकारी।

6. पी.डब्लू.-1, राम खिलाड़ी, वाद के प्रथम सूचनादाता ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि अभियुक्त उसके घर आता रहता था। घटना की तिथि पर, अभियुक्त उसके घर आया जब उसकी पत्नी, पुत्र-राकेश (मृतक) और राजू मौजूद थे। अभियुक्त भंडारे में शामिल होने के बहाने मृतक को ले गया। जब मृतक रात 09:00 बजे तक नहीं लौटा, तो वह मृतक के बारे में पूछताछ करने के लिए गिराज के पास गया, जिसने बताया कि वह टेम्पो चलाने गया है। उसके बाद, वह मृतक की तलाश में दरगाह गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने आगे बयान दिया कि जब प्रथम सूचनादाता अगले दिन सुबह 7:00 बजे फिर से गिराज के घर गया, तो वह मौजूद नहीं था और उसका दरवाजा बंद था और जब उसने खिड़की से अंदर देखा, तो उसका पुत्र चारपाई पर मृत पड़ा था और उसकी गर्दन के चारों ओर बिजली का तार लिपटा हुआ था।

7. पी.डब्लू.-2, श्रीमती माया देवी, जो मृतक की माता और प्रथम सूचनादाता की पत्नी है, पी.डब्लू.-3, बाबू लाल, पी.डब्लू.-4, राज कुमार, पी.डब्लू.-5, राजू, जो प्रथम सूचनादाता का पुत्र और मृतक का भाई है, पी.डब्लू.-8, भूरा उर्फ जलालुद्दीन, पी.डब्लू.-8ए, रामदीन, पी.डब्लू.-9, कुंवर पाल सिंह, जिनका तथ्य के साक्षीगण के रूप में परीक्षण किया गया है, ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया और अभियोजन पक्ष को उनसे जिरह करने की अनुमति दी गई।

8. पी.डब्लू.-7, डॉ. अजीत बाबा ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया है। उसने मृतक की गर्दन के चारों ओर ठुंडी से लगभग 6 सेमी नीचे 30 सेमी x 1-1/2 सेमी का लिंगेचर मार्क पाया। डॉक्टर की राय में, मृतक की मृत्यु का कारण गला घोटना था।

9. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के समाप्त होने के बाद, अभियुक्त-अपीलार्थी का बयान द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किया गया था, जिसमें उसने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इनकार किया और विचारण किए जाने का दावा किया।



10. विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 13, आगरा ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण, मूल्यांकन और संवीक्षा करने के बाद, अभियुक्त-अपीलार्थी को उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध किया और दण्डित किया।

11. अतः यह अपील प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी की ओर से तर्क

12. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध करते समय, अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत का विश्लेषण करने में गंभीर त्रुटि किया है। यह तर्क दिया गया है कि विचारण न्यायालय यह विचार करने में विफल रहा कि अपनी मुख्य परीक्षा में, पी.डब्ल्यू.-1, राम खिलाड़ी ने बयान दिया कि अपीलार्थी ने मृतक को 28.04.2012 को लगभग 02:00 बजे एक भंडारे में शामिल होने के लिए उसके साथ चलने को कहा था। पी.डब्ल्यू.-1 ने यह भी कहा कि अपीलार्थी उसकी पत्नी (श्रीमती माया देवी, पी.डब्ल्यू.-2) और पुत्र (राजू, पी.डब्ल्यू.-5) की उपस्थिति में उसके घर आया था, लेकिन, न तो पी.डब्ल्यू.-2, श्रीमती माया देवी और न ही पी.डब्ल्यू.-5, राजू ने अभियोजन पक्ष के इस प्रकरण का समर्थन किया कि अपीलार्थी मृतक को उक्त भंडारे में शामिल होने के लिए ले जाने हेतु उनके घर आया था।

13. आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यह विधि का एक स्थापित सिद्धांत है कि यदि किसी अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के प्रयोजन के लिए किसी पक्षद्रोही साक्षी के बयान पर भरोसा किया जाता है, तो ऐसे बयान की अन्य विश्वसनीय साक्ष्य, चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी, द्वारा संपुष्टि की जानी चाहिए। वर्तमान वाद में, पी.डब्ल्यू.-1, राम खिलाड़ी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में दिए गए बयान की किसी अन्य साक्षी या स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा संपुष्टि नहीं किया गया है। इसलिए, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध करते समय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचकर एक स्पष्ट त्रुटि कारित किया है।

14. आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी के कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई है। अभियोजन पक्ष द्वारा जो भी बरामदगी दिखाई गई है, वह केवल अपीलार्थी के कथित खाली घर से की गई है, न कि स्वयं अपीलार्थी के बताने पर या उसके कब्जे से की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

15. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि भले ही पी.डब्लू.-1 के बयान को सही मान लिया जाए कि अपीलार्थी उसके घर आया था और मृतक को 28.04.2012 को लगभग 02:00 बजे एक भंडारे में शामिल होने के लिए अपने साथ ले गया था, कथित तौर पर अंतिम बार देखे जाने के समय और डॉक्टर (पी.डब्लू.-7) द्वारा बताई गई मृत्यु के संभावित समय के बीच 12 घंटे से अधिक का अंतर है। इतना लंबा समय अंतराल अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत को लागू करने के लिए आवश्यक निकटता को पूरी तरह से तोड़ देता है। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष का संपूर्ण प्रकरण पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। इसलिए, यह अभियोजन पक्ष का दायित्व था कि वह परिस्थितियों की एक पूर्ण और अटूट श्रृंखला स्थापित करे जो केवल अपीलार्थी के दोष की ओर इशारा करती हो। हालांकि, अभियोजन पक्ष ऐसा करने में पूरी तरह विफल रहा है। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कथित अपराध कारित करने के लिए उद्देश्य का कोई साक्ष्य नहीं है। मृतक और अपीलार्थी के बीच कोई दुश्मनी या विवाद नहीं था। इसके विपरीत, मृतक और अपीलार्थी मित्र थे। पी.डब्लू.-2, श्रीमती माया देवी और पी.डब्लू.-5, राजू, अर्थात् सूचनादाता की पत्नी और पुत्र के माध्यम से यह साक्ष्य में आया है कि अपीलार्थी ने अपने खाली घर की देखभाल के लिए अपने घर की चाबी मृतक को सौंप दी थी।

16. आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कथित घटना की तिथि पर, अपीलार्थी अपने ससुराल में रह रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी वहां रह रही थी। घटनास्थल और वह स्थान जहां अपीलार्थी रह रहा था, लगभग 22 किलोमीटर दूर हैं। यह तथ्य अभियोजन पक्ष के प्रकरण को और कमजोर करता है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि जब उद्देश्य पूरी तरह से अनुपस्थित है, अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत का साक्षीगण द्वारा समर्थन नहीं किया जाता है, और कथित रूप से अंतिम बार देखे जाने और मृत्यु के समय के बीच 12 घंटे से अधिक का पर्याप्त समय अंतराल मौजूद है, तो अभियोजन पक्ष का प्रकरण अत्यधिक संदिग्ध हो जाता है। सभी तात्त्विक साक्षी पक्षद्रोही हो गए हैं, और यहां तक कि पी.डब्लू.-1 की मुख्य परीक्षा की किसी भी स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा संपुष्टि नहीं की गई है। परिणामस्वरूप, अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला को पूरा करने में विफल रहा है। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, घर स्वीकार्य रूप से खाली था, और घर की देखभाल करने के उद्देश्य से घर की चाबी मृतक के पास थी। यह तथ्य पी.डब्लू.-2 और पी.डब्लू.-5 ने भी अपनी

जिरह में कहा है। इस प्रकार, अपीलार्थी ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत अपने भार का पर्याप्त रूप से निर्वहन किया है।

17. आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पी.डब्ल्यू.-1 की मुख्य परीक्षा स्वयं विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि उसने कहा कि उसने मृतक के शव को कमरे की खिड़की से देखा था, हालांकि, नक्शा-नजरी के मात्र अवलोकन से पता चलता है कि उक्त घर में कोई खिड़की नहीं है। यह तात्विक विरोधाभास स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पी.डब्ल्यू.-1 की गवाही भरोसेमंद नहीं है और दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि संपूर्ण अभियोजन प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और परिस्थितियों की श्रृंखला अपूर्ण है, और सभी तात्विक साक्षी पक्षद्रोही हो गए हैं। बिना किसी विश्वसनीय या पुख्ता साक्ष्य के, केवल भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत उपधारणा के आधार पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधि की दृष्टि में कायम रखने योग्य नहीं है। इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं और वर्तमान अपील स्वीकार किए जाने योग्य है। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने *सुजीत बिस्वास बनाम असम राज्य (2013) 12 एस.सी.सी. 406*, *राज कुमार सिंह उर्फ राजू उर्फ बाट्या बनाम राजस्थान राज्य (2013) 5 एस.सी.सी. 722*, *रामरेड्डी राजेश खन्ना रेड्डी और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2006) 10 एस.सी.सी. 172* और *काली राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (1973) 2 एस.सी.सी. 808* के वादों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है।

राज्य की ओर से तर्क

18. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता एस.के. ओझा ने अपील का पुरजोर विरोध किया है और तर्क प्रस्तुत किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश में कोई त्रुटि या अवैधता नहीं है। यह आगे तर्क दिया गया है कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य और सामग्री पर विचार किया है और सही निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन पक्ष ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य की एक पूर्ण श्रृंखला स्थापित करके उचित संदेह से परे अपना प्रकरण साबित कर दिया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि अपनी मुख्य परीक्षा में, पी.डब्ल्यू.-1, राम खिलाड़ी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलार्थी लगभग 02:00 बजे उसके घर आया और मृतक को एक भंडारे में शामिल होने के लिए उसके साथ चलने को कहा, जिसके बाद



मृतक लापता था। उसके बाद, जब वह अपीलार्थी के घर गया, तो उसने मृतक को घर के अंदर मृत पड़ा पाया।

19. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी यह स्पष्ट करने में विफल रहा है कि मृतक को भंडारे में ले जाने के बाद क्या हुआ और उसके बाद वह अपने ससुराल के लिए निकल गया। अपीलार्थी उस समय और स्थान का खुलासा करने में भी विफल रहा है जब दोनों एक-दूसरे से अलग हुए। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि मृतक का शव अपीलार्थी के घर से बरामद किया गया था, इसलिए यह स्पष्ट करने का भार अपीलार्थी पर है कि किन परिस्थितियों में मृतक उसके घर के अंदर मृत पाया गया। अपीलार्थी इस भार का निर्वहन करने में विफल रहा है।

20. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता यह भी तर्क प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी ने यह स्थापित करने के लिए किसी भी बचाव पक्ष के साक्षी का परीक्षण नहीं कराया है कि प्रासंगिक समय पर वह या तो कहीं और मौजूद था या अपने ससुराल में रह रहा था। इसलिए, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध सही ढंग से प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला है और दर्ज की गई दोषसिद्धि में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

21. विद्वान ए.जी.ए. ने विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए आगे तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत उस पर डाले गए भार का निर्वहन करने में विफल रहा है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार, जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी अभियुक्त की जानकारी में होता है, तो ऐसे तथ्य को साबित करने का भार उस पर होता है। अभियोजन पक्ष के प्रकरण के अनुसार, मृतक का शव अपीलार्थी के घर से बरामद किया गया था। इसलिए, यह अपीलार्थी का दायित्व था कि वह यह स्थापित करने के लिए एक ठोस स्पष्टीकरण के साथ आगे आए कि वह अपराध कारित करने में संलिप्त नहीं था और उन परिस्थितियों को स्पष्ट करे जिनके अंतर्गत मृतक उसके घर के अंदर मृत पाया गया, जिसमें प्रासंगिक समय पर उसकी अनुपस्थिति या असंलिप्तता शामिल है। हालांकि, अपीलार्थी ऐसा कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम बलवीर सिंह (2025), आई.एन.एस.सी. 261** के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब दोष को साबित करने वाली परिस्थितियां अभियुक्त

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की विशेष जानकारी में होती हैं, तो ऐसी परिस्थितियों को स्पष्ट करने में विफलता न्यायालय को साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने की अनुमति देती है।

22. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि पी.डब्ल्यू.-1 के बयान ने "अंतिम बार देखे जाने" के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से स्थापित किया और यह कि अपीलार्थी के घर से शव की बरामदगी अस्पष्ट है। अपीलार्थी यह स्पष्ट करने में विफल रहा है कि मृतक उसके घर कैसे पहुंचा या किन परिस्थितियों में मृतक की मृत्यु वहां हुई। अपने तर्कों के समर्थन में, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने **चेतन बनाम कर्नाटक राज्य, 2025 आई.एन.एस.सी. 793** के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया है, यह तर्क देने के लिए कि एक बार जब अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला स्थापित कर देता है और अभियुक्त साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत भार का निर्वहन करने में विफल रहता है, तो दोषसिद्धि न्यायोचित है। इस प्रकार यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की संपूर्ण श्रृंखला अभियोजन पक्ष द्वारा विधिवत रूप से स्थापित की गई है, और अपीलार्थी साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत उस पर डाले गए भार का निर्वहन करने में विफल रहा है। इसलिए, आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं है और वर्तमान अपील खारिज किए जाने योग्य है।

विश्लेषण और निष्कर्ष

23. कथित अपराध का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। अपीलार्थी को केवल परिस्थितिजन्य/अंतिम बार देखे जाने वाले साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किया गया है और दण्डित किया गया है, जो विचारण न्यायालय के सुविचारित मत में, एक पूर्ण और अटूट श्रृंखला बनाता है ताकि अपीलार्थी के दोष के अलावा हर परिकल्पना को खारिज किया जा सके और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध कारित किए जाने की संभावना को बाहर किया जा सके।

24. अभियोजन पक्ष का प्रकरण पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित वाद में, स्थापित विधि यह है कि जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें पूरी तरह से साबित किया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां प्रकृति में निर्णायक होनी चाहिए। इसके अलावा, सभी परिस्थितियां एक श्रृंखला बनाते हुए पूर्ण होनी चाहिए और साक्ष्य की श्रृंखला में कोई अंतर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा, साबित परिस्थितियां केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के साथ संगत होनी चाहिए और उसकी बेगुनाही के साथ

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पूरी तरह से असंगत होनी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह लगातार प्रतिपादित किया गया है कि जहां कोई वाद परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, वहां दोष का निष्कर्ष तभी न्यायोचित ठहराया जा सकता है, जब सभी दोष सिद्ध करने वाले तथ्य और परिस्थितियां अभियुक्त की बेगुनाही या किसी अन्य व्यक्ति के दोष के साथ असंगत पाई जाती हों।

25. **शरद बिरधीचंद शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य**, ए.आई.आर. (1984) (एस.सी.) 1622 इस बिंदु पर एक प्रसिद्ध निर्णय है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के लिए पांच सुनहरे सिद्धांत विरचित किए हैं, जो इस प्रकार हैं;

(i) जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए।

(ii) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के साथ संगत होने चाहिए, अर्थात्, उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर स्पष्ट करने योग्य नहीं होना चाहिए, सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है।

(iii) परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए।

(iv) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभव परिकल्पना को बाहर करना चाहिए और,

(v) साक्ष्य की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की बेगुनाही के साथ संगत निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न बचे और यह दिखना चाहिए कि पूरी मानवीय संभावना में कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।

26. **पाडाला वीरा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य**, 1989 सप्ल (2) एस.सी.सी. 706 के वाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार राय व्यक्त किया:

"10. विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर ध्यान देने से पहले, हम शुरुआत में ही यह बताएंगे कि वर्तमान वाद में अभियुक्त को प्रश्नगत अपराध से जोड़ने के लिए कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है और अभियोजन पक्ष का प्रकरण पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। इस न्यायालय ने निर्णयों की एक श्रृंखला में लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि जब कोई वाद परिस्थितिजन्य साक्ष्य

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर आधारित होता है, तो ऐसे साक्ष्य को निम्नलिखित परीक्षाओं को पूरा करना चाहिए:

(1) जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे ठोस और दृढ़ता से स्थापित होनी चाहिए;

(2) वे परिस्थितियां एक निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए जो अचूक रूप से अभियुक्त के दोष की ओर इशारा करती हों;

(3) परिस्थितियों को संचयी रूप से लिया जाना चाहिए, और उन्हें इतनी पूर्ण श्रृंखला बनानी चाहिए कि इस निष्कर्ष से बचने का कोई उपाय न हो कि पूरी मानवीय संभावना के भीतर अपराध अभियुक्त द्वारा ही किया गया था और किसी अन्य द्वारा नहीं किया गया था; और

(4) परिस्थितिजन्य साक्ष्य दोषसिद्धि को कायम रखने के लिए पूर्ण होना चाहिए और अभियुक्त के दोष के अलावा किसी अन्य परिकल्पना के स्पष्टीकरण में अक्षम होना चाहिए और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के दोष के साथ संगत होना चाहिए बल्कि उसकी बेगुनाही के साथ असंगत भी होना चाहिए। (देखें **गंभीर बनाम महाराष्ट्र राज्य**, (1982) 2 एस.सी.सी. 351)"

27. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अशोक कुमार श्रीवास्तव, (1992) क्रि.एल.जे. 1104 में, यह बताया गया था कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मूल्यांकन करने में बहुत सावधानी बरती जानी चाहिए और यदि भरोसा किया गया साक्ष्य उचित रूप से दो निष्कर्षों के लिए सक्षम है, तो अभियुक्त के पक्ष में एक निष्कर्ष को स्वीकार किया जाना चाहिए। यह भी बताया गया कि जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित पाया जाना चाहिए और इस प्रकार स्थापित सभी तथ्यों का संचयी प्रभाव केवल दोष की परिकल्पना के साथ संगत होना चाहिए।

28. सी. चेंगा रेड्डी और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (1996) 10 एस.सी.सी. 193 के वाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित दोषसिद्धि के वाद पर विचार करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"21. परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित वाद में, स्थापित विधि यह है कि जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें पूरी तरह से साबित किया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां प्रकृति में निर्णायक होनी चाहिए। इसके अलावा, सभी परिस्थितियां पूर्ण होनी चाहिए और साक्ष्य की श्रृंखला में कोई अंतर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा, साबित परिस्थितियां केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के साथ संगत होनी चाहिए और उसकी बेगुनाही के साथ पूरी तरह से असंगत होनी चाहिए। वर्तमान वाद में अवर न्यायालयों ने इन स्थापित सिद्धांतों की अनदेखी की है और कुछ अस्वीकार्य साक्ष्य पर भरोसा करने के अलावा संदेह को साक्ष्य का स्थान लेने की अनुमति दिया है।"

29. **रामरेड्डी राजेश खन्ना रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य**, (2006) 10 एस.सी.सी. 172 के वाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित दोषसिद्धि के प्रकरण पर विचार किया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"26. अब यह भली-भांति स्थापित है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के लिए, अभियोजन पक्ष को विश्वसनीय और पुख्ता साक्ष्य द्वारा दोष सिद्ध करने वाली परिस्थितियों के सभी हिस्सों को स्थापित करना चाहिए और इस प्रकार साबित परिस्थितियों को घटनाओं की ऐसी श्रृंखला बनानी चाहिए, जो अभियुक्त के दोष के अलावा किसी अन्य निष्कर्ष की अनुमति न दे। परिस्थितियां किसी अन्य परिकल्पना पर नहीं हो सकती हैं। यह भी भली-भांति स्थापित है कि संदेह, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, साक्ष्य का विकल्प नहीं हो सकता है और न्यायालय केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी अभियुक्त को दोषी पाते समय अत्यधिक सावधानी बरतेंगे। (देखें **अनिल कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य**, (2003) 9 एस.सी.सी. 67 और **रेड्डी सम्पत कुमार बनाम आंध्र प्रदेश राज्य**, (2005) 7 एस.सी.सी. 603)।"

30. **सततिया बनाम महाराष्ट्र राज्य**, (2008) 3 एस.सी.सी. 210 के वाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"10. हमने संपूर्ण मामले पर विचार किया है। यह स्थापित विधि है कि किसी अपराध को न केवल प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा बल्कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा भी साबित किया जा सकता है, जहां कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। न्यायालय दोष का निष्कर्ष तब निकाल सकता है जब सभी दोष सिद्ध करने वाले तथ्य और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परिस्थितियां अभियुक्त की बेगुनाही के साथ पूरी तरह से असंगत पाई जाती हों।
बेशक, जिन परिस्थितियों से दोष के संबंध में निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें उचित
संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए और उन्हें उस मुख्य तथ्य से निकटता से
जुड़ा हुआ दिखाया जाना चाहिए जिसका उन परिस्थितियों से निष्कर्ष निकाला जाना
है।" इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में आगे टिप्पणी किया कि:

"17. इस चरण पर, हम यह भी टिप्पणी करना उचित समझते हैं कि संविधान के
अनुच्छेद 136 के अंतर्गत शक्ति के प्रयोग में, यह न्यायालय दोषसिद्धि के उस
निर्णय को उलटने के लिए अत्यधिक अनिच्छुक होगा, जिसकी अपील में पुष्टि की
गई है। हालांकि, यदि यह पाया जाता है कि किसी वाद में साक्ष्य का मूल्यांकन,
जो पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, गंभीर त्रुटियों से दूषित है
और उस कारण न्याय की विफलता हुई है, तो न्यायालय निश्चित रूप से विचारण
न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज समवर्ती निष्कर्षों में भी हस्तक्षेप करेगा-
-भरत बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2003) 3 एस.सी.सी. 106।"

31. रामबृक्ष उर्फ जालिम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, 2016(12) एस.सी.सी. 251 में, माननीय सर्वोच्च
न्यायालय ने टिप्पणी किया कि अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत तभी लागू होता है, जब अंतिम
बार देखे जाने के बिंदु और मृत्यु की खोज के बीच का समय अंतराल इतना कम हो कि कोई और
अपराध कारित नहीं कर सकता था। तब भी, केवल यह परिस्थिति अपर्याप्त है और अभियोजन
पक्ष को अभियुक्त के दोष को साबित करने वाली परिस्थितियों की एक पूर्ण श्रृंखला स्थापित करनी
चाहिए। न्यायालय ने आगे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"यह स्थापित विधि है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध केवल इस आधार पर
दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती है कि अभियुक्त को अंतिम बार मृतक के साथ
देखा गया था। दूसरे शब्दों में, केवल अंतिम बार एक साथ देखे जाने की परिस्थिति
के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है। सामान्यतः, अंतिम बार देखे जाने
का सिद्धांत तब लागू होता है, जब उस समय बिंदु, जब अभियुक्त और मृतक को
अंतिम बार जीवित देखा गया था और जब मृतक मृत पाया जाता है, के बीच का
समय अंतराल इतना कम होता है कि अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के
अपराध का अपराधी होने की संभावना असंभव हो जाती है। दोषसिद्धि दर्ज करने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया
जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के लिए, केवल अंतिम बार एक साथ देखा जाना पर्याप्त नहीं होगा और अभियोजन पक्ष को अभियुक्त का दोष पूरी तरह से साबित करने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करना होगा।"

32. कृष्णन उर्फ रामासामी और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य, (2014)12 एस.सी.सी. 279 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अर्जुन मारिक बनाम बिहार राज्य, 1994 सप्ल (2) एस.सी.सी. 372 में अपने पूर्व के निर्णय पर भरोसा करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"इस प्रकार, यह साक्ष्य कि अपीलार्थी 19.07.1985 की शाम को सीताराम के पास गया था और रात में मृतक सीताराम के घर पर रुका था, बहुत अस्थिर और अनिर्णायक है। भले ही यह मान लिया जाए कि वे वहां थे, यह ज्यादा से ज्यादा अपीलार्थियों को मृतक के साथ अंतिम बार देखे जाने का साक्ष्य होगा। लेकिन, यह स्थापित विधि है कि केवल अंतिम बार देखे जाने की परिस्थिति इस निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा नहीं करेगी कि यह केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के साथ संगत है और इसलिए, केवल उस आधार पर कोई दोषसिद्धि स्थापित नहीं की जा सकती है।"

33. कन्हैया लाल बनाम राजस्थान राज्य, (2014) 4 एस.सी.सी. 715 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अंतिम बार एक साथ देखे जाने का साक्ष्य एक कमजोर साक्ष्य है और अभियुक्त के विरुद्ध किसी अन्य संपोषक साक्ष्य के बिना केवल अंतिम बार एक साथ देखे जाने के आधार पर दोषसिद्धि अभियुक्त को धारा 302 और 201 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध के लिए दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

34. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के आलोक में, हम अब विचार करेंगे कि क्या वर्तमान वाद में, अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की श्रृंखला को स्थापित करने में सफल रहा है, जो इस अपरिहार्य निष्कर्ष की ओर ले जाती है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने अपराध कारित किया था।

35. पी.डब्ल्यू.-1 राम खिलाड़ी वाद का प्रथम सूचनादाता है। वह वाद का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। उसने बयान दिया कि अपीलार्थी उसके घर आता-जाता था। उसने घटना से एक दिन पहले उसके घर का दौरा किया और उसकी पत्नी, पी.डब्ल्यू.-2, श्रीमती माया देवी और उसके पुत्र, पी.डब्ल्यू.-5,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



राजू की उपस्थिति में उसके पुत्र को अपने साथ ले गया। उसने आगे बयान दिया कि रात में जब वह मृतक के बारे में पूछताछ करने के लिए अपीलार्थी के घर गया, तो उसे बताया गया कि मृतक टेम्पो चलाने गया है। उसके बाद, उसने दरगाह के पास मृतक की तलाश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने आगे बयान दिया कि जब वह अगले दिन सुबह अपीलार्थी के घर गया, तो अपीलार्थी का घर बंद था और जब उसने खिड़की से अंदर देखा, तो उसका पुत्र चारपाई पर मृत पड़ा था।

36. पी.डब्लू.-2, माया देवी मृतक की माता है और घटना की चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। उसने बयान दिया कि वह अभियुक्त-अपीलार्थी को नहीं जानती है। वह उसके पुत्र, मृतक को बुलाने के लिए उसके घर नहीं आया था। उसने आगे बयान दिया कि न तो वह अभियुक्त की तलाश में गई और न ही उसने घटना देखी। वह अभियुक्त-अपीलार्थी को भी नहीं जानती है। उपरोक्त बयान पर, उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया और उसने अपीलार्थी के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं कहा है।

37. इसी प्रकार, पी.डब्लू.-3, बाबू लाल, पी.डब्लू.-4 राज कुमार, पी.डब्लू.-5, राजू, मृतक का भाई, पी.डब्लू.-8, भूरा उर्फ जलालुद्दीन, पी.डब्लू.-8ए, रामदीन और पी.डब्लू.-9, कुंवर पाल सिंह ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

38. यह स्थापित विधि है कि यदि किसी पक्षद्रोही साक्षी का साक्ष्य अभियोजन पक्ष या अभियुक्त के पक्ष में बोला जाता है, तो उसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया जाएगा। इसके बजाय इसे बारीकी से संवीक्षा के अधीन किया जाना चाहिए और साक्ष्य का वह भाग, जो अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष के प्रकरण के साथ संगत है, स्वीकार किया जा सकता है।

39. **खुज्जी उर्फ सुरेंद्र तिवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य**, 1991(3) एस.सी.सी. 627 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष के किसी साक्षी के साक्ष्य को पूरी तरह से केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि अभियोजन पक्ष ने उसे पक्षद्रोही मानने और उससे जिरह करने का विकल्प चुना। ऐसे साक्षीगण के साक्ष्य को अभिलेख से पूरी तरह से मिटा हुआ या साफ किया हुआ नहीं माना जा सकता है, लेकिन इसे इस सीमा तक स्वीकार किया जा सकता है कि उनका वृत्तांत सावधानीपूर्वक संवीक्षा पर भरोसेमंद पाया जाता है।

40. **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रमेश प्रसाद मिश्रा**, (1996)10 एस.सी.सी. 360 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जाएगा यदि वह अभियोजन या अभियुक्त के पक्ष में बोला गया है, बल्कि उसे बारीकी से संवीक्षा के अधीन किया जाना आवश्यक है और साक्ष्य का वह भाग जो अभियोजन या बचाव के प्रकरण के साथ संगत है, उस पर भरोसा किया जा सकता है।"

41. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सेल्वमणी बनाम राज्य द्वारा पुलिस महानिरीक्षक**, 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 837 में, निर्णयों की एक श्रृंखला पर विचार करने के बाद अभिनिर्धारित किया कि इस बिंदु पर विधि को इस प्रभाव तक संक्षेपित किया जा सकता है कि किसी पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य को समग्र रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है, और उसके प्रासंगिक भागों का उपयोग जो विधि में स्वीकार्य हैं, अभियोजन या बचाव द्वारा किया जा सकता है।

42. इस वाद में, पी.डब्लू.-2, श्रीमती माया देवी, जो प्रथम सूचनादाता की पत्नी और मृतक की माता है, ने अपने बयान में अभियोजन पक्ष के प्रकरण से पूरी तरह इनकार किया है। इसके अलावा, पी.डब्लू.-3, बाबू लाल, पी.डब्लू.-4 राज कुमार, पी.डब्लू.-5, राजू, मृतक का भाई, पी.डब्लू.-8, भूरा उर्फ जलालुद्दीन, पी.डब्लू.-8ए, रामदीन और पी.डब्लू.-9, कुंवर पाल सिंह ने भी अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। किसी भी साक्षी ने अपने बयान में वर्तमान वाद में अभियुक्त-अपीलार्थी की भागीदारी के बारे में कोई भनक नहीं दी है। यहां तक कि पी.डब्लू.-2, माया देवी, जो प्रथम सूचनादाता की पत्नी और मृतक की माता है और पी.डब्लू.-5, राजू, मृतक का भाई, ने अपीलार्थी के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं कहा है। इसके अलावा, पी.डब्लू.-2, माया देवी ने अपनी जिरह में कहा है कि उसके पति, सूचनादाता ने गलत तरीके से एफ.आई.आर. में अपीलार्थी का नाम लिखवाया है और अपीलार्थी मृतक को अपने साथ नहीं ले गया है। अपनी जिरह में, उसने आगे बयान दिया है कि अपीलार्थी अपने ससुराल में रहता है और उसके घर की चाबी मृतक के पास थी। पी.डब्लू.-1, राम खिलाड़ी के साक्ष्य की किसी अन्य विश्वसनीय साक्षी द्वारा चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी रूप में, संपुष्टि नहीं की गई है। यहां तक कि पी.डब्लू.-1, सूचनादाता ने, अपनी जिरह में, जो 18.01.2016 को की गई थी, विशेष रूप से बयान दिया है कि घटना की तिथि पर, उसके दोनों पुत्र अर्थात् राकेश (मृतक) और राजू (पी.डब्लू.-5) टेंट हाउस गए थे, जहां वे काम कर रहे थे। राजू (पी.डब्लू.-5) शाम को लौट आया, लेकिन उसने राकेश के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ठिकाने के बारे में नहीं बताया। पी.डब्लू.-1 ने यह भी कहा कि उसे नहीं पता था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में क्या लिखा था। एफ.आई.आर. की विषयवस्तु उसे पढ़कर नहीं सुनाई गई। वह मुकेश को भी नहीं जानता है, जिसने रिपोर्ट लिखा है। रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल द्वारा लिखवाई गई थी। उसके पुत्र का शव सड़क पर पड़ा था।

43. पी.डब्लू.-1, राम खिलाड़ी के बयान के संयुक्त पठन से, यह स्पष्ट है कि न तो वह अंतिम बार देखे जाने का साक्षी था, और न ही उसने मृतक के शव को देखा था जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभिकथन किया गया है।

44. हम यह भी पाते हैं कि अपीलार्थी के पास मृतक की हत्या कारित करने का कोई उद्देश्य नहीं था। इसके अलावा, मृतक का अपीलार्थी के साथ कोई विवाद या दुश्मनी नहीं थी, बल्कि वे घनिष्ठ मित्र थे और अपीलार्थी के घर की चाबी मृतक के पास थी जैसा कि पी.डब्लू.-2, माया देवी और पी.डब्लू.-5 राजू ने बयान दिया है कि अपीलार्थी ने अपने खाली घर की देखभाल के लिए अपने घर की चाबी मृतक को सौंप दिया था।

45. जहां तक विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के इस तर्क का संबंध है कि यह अपीलार्थी का दायित्व था कि वह यह स्थापित करने के लिए एक ठोस स्पष्टीकरण के साथ आगे आए कि वह अपराध कारित करने में संलिप्त नहीं था और उन परिस्थितियों को स्पष्ट करे जिनके अंतर्गत मृतक उसके घर के अंदर मृत पाया गया था। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता का यह तर्क वर्तमान वाद के तथ्यों में टिकने योग्य नहीं है क्योंकि किसी भी अभियोजन साक्षी ने अपनी गवाही में यह बयान नहीं दिया है कि शव अपीलार्थी के घर से बरामद किया गया था और कि अपीलार्थी मृतक को भंडारे में शामिल होने के लिए ले गया था, और वे अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत के अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं करते हैं।

46. यह आपराधिक न्यायशास्त्र का एक प्रमुख सिद्धांत है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 लागू होगी और स्पष्ट करने का भार अभियुक्त पर तभी स्थानांतरित होगा जब अभियोजन पक्ष उन मूलभूत तथ्यों को स्थापित करने में सफल हो जाता है, जिनसे कुछ अन्य तथ्यों के अस्तित्व के संबंध में एक उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है जो अभियुक्त की विशेष जानकारी में हैं। वर्तमान वाद में, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष मूलभूत तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए अभियुक्त पर भार स्थानांतरित करने में पूरी तरह विफल रहा है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



47. सावल दास बनाम बिहार राज्य, (1974) 4 एस.सी.सी. 193 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"हालांकि, साक्ष्य अधिनियम की न तो धारा 103 और न ही 106 का अनुप्रयोग अभियोजन पक्ष को अभियोजन के प्रकरण को उचित संदेह से परे साबित करने के अपने सामान्य या प्राथमिक भार का निर्वहन करने के कर्तव्य से मुक्त कर सकता है। यह केवल तभी होता है जब अभियोजन पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करता है जो, यदि विश्वास किया जाता है, तो दोषसिद्धि को कायम रखेगा, या, जो प्रथम दृष्टया वाद बनाता है, कि उन तथ्यों पर विचार करने का प्रश्न उठता है जिन्हें साबित करने का भार अभियुक्त पर हो सकता है।"

48. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गार्गी बनाम हरियाणा राज्य, 2019(3) एस.सी.सी. (क्रि.) 785 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

"जहां तक 'अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत' का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी मृतक की पत्नी होने के नाते और एक ही छत के नीचे रहने के कारण, वह अंतिम व्यक्ति थी जिसके साथ मृतक को देखा गया था। हालांकि, मृतक और अपीलार्थी का ऐसा साथ, अपने आप में, इसका मतलब यह नहीं है कि अपीलार्थी के दोष की उपधारणा निकाली जानी है। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय इस धारणा पर आगे बढ़े हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 सीधे अपीलार्थी के विरुद्ध संचालित होती है। हमारे विचार में, ऐसा दृष्टिकोण भी त्रुटि से मुक्त नहीं रहा है जहां यह विचार करना छोड़ दिया गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 अभियोजन पक्ष को उसके प्राथमिक भार से मुक्त नहीं करती है।"

49. हमने अभियोजन पक्ष के सभी साक्षीगण के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक संवीक्षा और आकलन किया है। इस न्यायालय का विचार है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में न तो गुणवत्ता है और न ही विश्वसनीयता और ऐसे साक्ष्य पर दोषसिद्धि को आधारित करना असुरक्षित होगा। मामले पर विचारपूर्वक विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि वाद में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य अपीलार्थी का दोष पूरी तरह से साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



50. तदनुसार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 13, आगरा द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 320 वर्ष 2012, अंतर्गत धारा 302 भा.द.सं., थाना सिकंदरा, जनपद आगरा से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 380 वर्ष 2012 में पारित आदेश दिनांक 14.12.2017 अपास्त किया जाता है।

51. अपील स्वीकार की जाती है।

52. अपीलार्थी गिराज सिंह कारागार में है। यदि वह किसी अन्य वाद में वांछित नहीं है तो, उसे तत्काल रिहा किया जाए।

53. कार्यालय को अनुपालन के लिए संबंधित न्यायालय को विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ इस आदेश की एक प्रति प्रेषित करने और अनुपालन आख्या दो माह के भीतर इस न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-I) (न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह)

14 जनवरी, 2026

इशरत